कानपुर, बुधवार, 11 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 41, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ बढ़ाया...>Pg12

नाली तक मकान फुटपाथ पर रैंप ...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

10 लाख युवाओं को रोजगार का ऐलान, बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए

₹9.12 लाख करोड़: अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार का यह दसवां बजट सदन में रखा। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक बताया गया है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों में भर्तियां, कौशल विकास कार्यक्रम और निवेश आधारित रोजगार सृजन योजनाएं चलाई जाएंगी।

बजट सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल भी गरम रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सपा

नेता शिवपाल यादव ने बजट को चुनावी बजट बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना है और जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा।

वादों की परीक्षा अब क्रियान्वयन में

यह बजट आकार और घोषणाओं के लिहाज से ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। अगर रोजगार के अवसर वास्तविक रूप में सामने आए, सामाजिक योजनाओं का लाभ समय पर मिले और नई परियोजनाएं धरातल पर दिखें तो यह बजट 2027 के राजनीतिक समीकरण तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

बजट का आकारः आर्थिक विस्तार का संकेत

लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ पेश किया गया यह बजट राज्य की बढ़ती राजस्व क्षमता और निवेश आकर्षण का संकेत देता है। बड़ा बजट यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की स्थिति में है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बजट का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राजस्व संग्रह और व्यय प्रबंधन कितना संतुलित रहता है।

चुनावी संदर्भः विकास बनाम सियासत

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुआ यह बजट स्वाभाविक रूप से राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। विपक्ष इसे "चुनावी बजट" करार दे रहा है, जबकि सरकार इसे "विकास का रोडमैप" बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा और महिला वर्ग को केंद्र में रखकर सरकार ने मजबूत सामाजिक गठजोड़ साधने की कोशिश की है। बड़े बजट के जरिए विकास की निरंतरता का संदेश दिया गया है।

10 लाख रोजगारः वादा या व्यवहारिक योजना?

10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा बजट की सबसे प्रमुख बात है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, जहां हर साल बड़ी संख्या में युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। क्या ये रोजगार सरकारी भर्तियों से होंगे या निजी निवेश के माध्यम से? क्या कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ा गया है? रोजगार का टाइमलाइन और मॉनिटरिंग तंत्र क्या होगा? यदि यह लक्ष्य चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू हुआ, तो यह सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक और सामाजिक लाभ साबित हो सकता है।

43 हजार करोड़ की नई योजनाएं विकास का इंजन

नई योजनाओं में बुनियादी ढांचा, कृषि, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और महिला-युवा केंद्रित कार्यक्रम शामिल हैं। इस बजट का संभावित असर यह होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा और सोलर और ऊर्जा परियोजनाओं से दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। यह निवेश यदि समय पर जमीन पर उतरा तो प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर को मजबूती मिल सकती है।

बेटियों की शादी सहायता सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

शादी सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना सीधे तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने का प्रयास है।

रोजगार, महिला सशक्तिकरण और चुनावी समीकरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया 9.12 लाख करोड़ का बजट केवल आंकड़ों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह योगी आदित्यनाथ सरकार का दसवां बजट है और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट भी। ऐसे में इस दस्तावेज को विकास और राजनीति–दोनों नजरियों से देखा जा रहा है।

अवैध प्लाटिंग माफिया पर सख्त कार्रवाई

रवि प्रताप सिंह बने बुलडोजर मैन

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-1बी के विशेष कार्याधिकारी व उपजिलाधिकारी डा0 रवि प्रताप सिंह इन दिनों अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में हैं। शहर में अवैध प्लाटिंग माफिया के विरुद्ध उनकी लगातार कार्रवाई के चलते उन्हें अब ‘बुलडोजर मैन’ के रूप में पहचाना जाने लगा है।हाल ही में उनके नेतृत्व में बैकुण्ठपुर और बगदौंधी बांगर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने परिसरों को सील किया गया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।

रवि प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रवर्तन टीम द्वारा लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, कब्जे और बिना अनुमति किये जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई स्थानों पर नोटिस जारी कर चेतावनी भी दी गयी है कि निर्धारित समय में जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से अवैध प्लाटिंग माफिया सक्रिय थे, लेकिन अब सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबार पर रोक लग रही है और व्यवस्था में सुधार दिख रहा है।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एसआईआर में तकनीकी अड़चन, युवा व नवविवाहित नहीं बन पा रहे मतदाता

मैपिंग त्रुटियों से 412 शिकायतें, माता-पिता के पुराने रिकॉर्ड न होने पर अटके

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। प्रदेश में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की अवधि भले एक माह बढ़ा दी गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर तकनीकी खामियों और डेटा मैपिंग की समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में युवा और नवविवाहित महिलाएं मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पा रही हैं। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद आवेदकों को बार-बार तहसील और बीएलओ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

सबसे अधिक दिक्कत उन आवेदकों को हो रही है जिनके माता-पिता का निधन वर्ष 2003 से पहले हो चुका है या जिनका नाम पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हुआ था। ऐसे मामलों में ÷मैपिंग÷ न हो पाने से आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं।

भाजपा उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 412 शिकायतें दर्ज की गई हैं। भाजपा दक्षिण जिला के मीडिया प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि विभागीय तकनीकी खामियों के कारण पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर रह जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नाम विलोपन अधिक हुआ है, वहीं तकनीकी त्रुटियों की संख्या भी ज्यादा है। उन्होंने प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र समाधान की मांग की है। वहीं कैंट क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार निवासी सुशील कुमार ने बताया कि शाहजहांपुर प्रवास के दौरान बीएलओ की त्रुटि से उनके नाम में गलती दर्ज हो गई थी। अब फार्म-8 के माध्यम से सुधार कराने में तीन माह तक का समय बताया जा रहा है।

न्यू आजाद नगर निवासी लियोनेल एलबर्ट बेलेटी ने बताया कि आधार, पैन, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज होने के बावजूद उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा। उनके माता-पिता का निधन 2003 से पूर्व हो चुका है, जिससे रिकॉर्ड सत्यापन में बाधा आ रही है। कोयलानगर की मंजू लता, जिनकी शादी पिछले वर्ष हुई, भी नाम जुड़वाने के लिए परेशान हैं। उनके पिता सरकारी सेवा में थे और तबादलों के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो सका। दोनों अभिभावकों के निधन के कारण अब मैपिंग संभव नहीं हो पा रही।

फेथफुलगंज रेलवे कॉलोनी के 73 वर्षीय रामजनम त्रिपाठी ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र, बिजली बिल, पेंशन दस्तावेज, आधार और बैंक पासबुक देने के बावजूद नाम दर्ज न होने की शिकायत की है। वहीं छावनी क्षेत्र के 20 वर्षीय अनुभव तिवारी ने बताया कि सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी पिता की मैपिंग न होने से आवेदन लंबित है। लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच विशेष सत्यापन अभियान और तकनीकी सुधार की मांग तेज हो गई है, ताकि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस-वे पर मिली युवती की लाश का खुलासा

लिव-इन साथी ने की थी गला दबाकर हत्या

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। दिल्ली में मिली 25 वर्षीय युवती की सड़ी-गली लाश के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की हत्या उसके लिव-इन साथी ने ही गला दबाकर की थी और बाद में शव को थार गाड़ी से आगरा ले जाकर एक्सप्रेस-वे किनारे फेंक दिया।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान सोनाली के रूप में हुई है, जो 28 वर्षीय सनी के साथ दिल्ली में किराए के कमरे में रह रही थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और वे लिव-इन में रह रहे थे। 6 फरवरी को पुलिस को एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जो काफी सड़ चुका था और चेहरे पर चोट के निशान होने के कारण पहचान मुश्किल थी।जांच के दौरान पुलिस ने तकनीक की मदद से चेहरा पुनर्निर्मित कराया, जिसके बाद पहचान संभव हो सकी और पुलिस आरोपी सनी तक पहुंच गई। पूछताछ में पहले उसने आत्महत्या की कहानी बताई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर वह टूट गया और अपराध कबूल कर लिया।आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और बाद में परिवार महोबा चला गया था, जहां उसकी मुलाकात सोनाली से हुई थी। दोनों दिल्ली आकर साथ रहने लगे थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी सोनाली को देह व्यापार के गिरोह में धकेलना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे आशंका थी कि युवती उसकी करतूतों का खुलासा कर देगी, इसी डर से उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने यह भी बताया कि हत्या के बाद उसकी मां और सौतेले पिता ने शव ठिकाने लगाने में मदद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।

तात्याटोपे नगर

नाली तक मकान फुटपाथ पर रैंप

प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक फुटपाथ पर अतिक्रमण से बेहाल नागरिक

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (के डी ए) की योजना 'तात्या टोपे नगर' इन दिनों अवैध अतिक्रमण की चपेट में है। अच्छा इलाका होने के बावजूद यहाँ के गृह स्वामियों द्वारा प्रमुख सड़कों और अधिकतर गलियों के किनारों पर किए गए कब्जों ने आम राहगीरों और यातायात के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।

क्षेत्र का जायजा लेने पर यह साफ झलकता है कि योजना के तहत पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। कई मकान मालिकों ने अपने घर के सामने के फुटपाथ पर पक्का निर्माण कर उसे निजी बगीचे, पार्किंग या रैंप में तब्दील कर दिया है। इसके कारण पैदल चलने वाले लोग मुख्य सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है।

➪ अधिकतर गलियों में नालियां हैं नदारद, नालियों पर निर्माण से जलभराव का संकट

अतिक्रमण का सबसे बुरा असर क्षेत्र की जलनिकासी व्यवस्था पर पड़ा है। अधिकांश भवन स्वामियों ने नालियों के ऊपर पक्के स्लैब या चबूतरे बना लिए हैं। नालियां पूरी तरह ढंक जाने के कारण नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इन्हें साफ करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। नालियों के भीतर कचरा जमा होने और उनकी नियमित सफाई न हो पाने के कारण आए दिन गलियों में गंदा पानी भरा रहता है, जो बीमारियों को न्योता दे रहा है।

क्षेत्रीय पार्षद के मौन पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय पार्षद कविता चौहान और उनके पति वीरेंद्र सिंह को इस स्थिति की पूरी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई स्थानीय लोगों ने नाम का खुलासा न करने बात कहते हुए प्रशासन से मांग की है कि वह तत्काल पैमाइश करवाकर अवैध कब्जों को ढहाए और फुटपाथों को आम जनता के लिए मुक्त कराए।

लैंबॉर्गिनी केस में ड्राइवर के सरेंडर से आया नया मोड़

स्वराज इंडिया फालोअप

➪ कोर्ट में ड्राइवर मोहन ने दावा किया कि गाड़ी मैं चला रहा था

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट मामले में बुधवार को अहम घटनाक्रम सामने आया। अब तक पुलिस जांच में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के पुत्र शिवम मिश्रा को वाहन चालक बताया जा रहा था, लेकिन बुधवार को मोहन नामक युवक ने अदालत में सरेंडर कर दावा किया कि दुर्घटना के समय वही गाड़ी चला रहा था। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि घटना के बाद दर्ज एफआईआर में शुरू में केवल वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख था। चालक का नाम स्पष्ट नहीं किया गया था। मामला मीडिया में आने के बाद जांच तेज हुई और पुलिस ने उपलब्ध वीडियो फुटेज, तकनीकी साक्ष्य व अन्य तथ्यों के आधार पर शिवम मिश्रा को चालक बताया। पुलिस कमिश्नर स्तर से भी यह कहा गया था कि जांच में शिवम के वाहन चलाने के प्रमाण मिले हैं। दूसरी ओर, शिवम मिश्रा के परिवार ने शुरू से ही इस दावे का खंडन किया था। परिवार का कहना था कि शिवम घटना के समय वाहन नहीं चला रहे थे और उन्हें अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया जा रहा है। परिवार ने पुलिस पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था।

अब मोहन के सरेंडर और अदालत में दिए गए बयान के बाद मामले की दिशा बदलती दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोहन के बयान का सत्यापन किया जाएगा और उसे उपलब्ध डिजिटल व फॉरेंसिक साक्ष्यों से मिलाया जाएगा। यदि बयान साक्ष्यों से मेल खाता है तो विवेचना में संशोधन किया जा सकता है। वहीं, यदि तथ्य विपरीत पाए गए तो कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाई-प्रोफाइल बन चुके इस मामले में अब सभी की नजर पुलिस की अगली जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी है।

साइबर-इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी

आईआईटी कानपुर बनेगा सेना का टेक पार्टनर

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। भविष्य के युद्धों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और साइबर व इलेक्ट्रॉनिक डोमेन अब रणनीतिक मोर्चे के केंद्र में आ गए हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस क्रम में आईआईटी कानपुर सेना का तकनीकी साझेदार बनने जा रहा है।

संस्थान के वैज्ञानिक और इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मानव रहित ऑटोनामस सिस्टम जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप शोध एवं विकास कार्य करेंगे। दोनों संस्थानों के बीच औपचारिक समझौते (एमओयू) की प्रक्रिया जल्द पूरी होने के संकेत हैं।

भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने आईआईटी कानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. तरुण गुप्ता और नोडल फैकल्टी प्रभारी प्रो. कांतेश बलानी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा अनुसंधान, नवाचार, स्वदेशी तकनीक विकास और सैन्य आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उप सेनाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अधिक लड़े जाएंगे। ऐसे में सेना को तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना समय की आवश्यकता है।

आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में

➪ एआई, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोनामस सिस्टम पर सेना की जरूरत अनुसार होगा शोध

विकसित अत्याधुनिक प्रणालियों ने भी सेना का ध्यान आकर्षित किया। विशेषज्ञों ने मानवरहित हेलीकॉप्टर, वीटीओएल (वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग) सिस्टम और यूएवी (अनमैंड एरियल व्हीकल) आधारित परियोजनाओं की जानकारी दी। आपदा प्रबंधन, युद्धक अभियानों और सर्विलांस के लिए विकसित ड्रोन मॉडलों की क्षमताओं पर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा सी3आई (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस) हब के विशेषज्ञों ने उन्नत साइबर सुरक्षा ढांचे, सुरक्षित संचार प्रणाली और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विकसित तकनीकों से सेना के अधिकारियों को अवगत कराया। तकनीकी सहयोग की यह पहल आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र और स्वदेशी नवाचार को नई गति देने वाली मानी जा रही है।

गज़ब! 22 गज जगह में बहुमंजिला इमारत, नीचे दुकानें ऊपर फ्लैट्स

» पैसे के लालच में बिल्डर कर रहे हैं इंसानी जिंदगी से खिलवाड़

» संकरी गलियों में खड़ी हो रहीं मौत की इमारतें, केडीए की लापरवाही पर सवाल

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

» पटकापुर चौकी के पास महज़ 22 गज जगह में खड़ी हो गई बहुमंजिला इमारत

कानपुर। शहर का संवेदनशील इलाका पटकापुर, जहां पर हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों की मिलीजुली आबादी है, वहां बिल्डर नेटवर्क की दबंगई आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। पटकापुर चौकी के पास शनि देव मंदिर के सामने महज़ 22 गज की जगह पर नीचे दुकानें, ऊपर फ्लैट्स यानी की बहुमंजिला इमारत आसपास के लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, हादसे की आशंका सबको सता रही है। इतनी कम जगह में फ्लैट्स कैसे बने, इसका जुगाड़ भी बिल्डर ने कर लिया है। जितनी जगह है उससे कई फुट लंबा छज्जा निकाल दिया है और उस पर वन बीएचके तैयार हो गया। यह निर्माण तो महज एक बानगी है ऐसी दर्जनों बहुमंजिला इमारतें बनकर तैयार हो गई है या फिर बन रही हैं।

शहर में अवैध और खतरनाक निर्माण अब सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सीधे इंसानी जिंदगी पर हमला बनता जा रहा है। पटकापुर इलाके से सामने आए मामलों ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की कार्यप्रणाली, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 20, 30, 40, 50, 60, 80 गज जैसे बेहद छोटे भूखंडों पर बहुमंजिला

इमारतें खड़ी कर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिनमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कम बजट के लालच में रहने को मजबूर हैं।

पूर्व पार्षद के गठजोड़ से अवैध निर्माण का बड़ा काकस

स्थानीय चर्चा में यह भी सामने आ रहा है कि निर्माण कार्य सपा के पूर्व पार्षद मन्नू रहमान का खास गुर्गा प्यारे सीधे अपने नाम से न कराकर एक अन्य व्यक्ति को आगे कर काम कराया जा रहा है, ताकि हिंदू बाहुल्य इलाकों में विरोध और जांच से बचा जा सके। आरोप है कि इस तरीके से खासतौर पर घनी बस्तियों और संवेदनशील इलाकों में निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिल्डर नेटवर्क की दबंगई के कारण आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने छोटे प्लॉट पर इतनी ऊंची इमारतें किस नक्शे, किस अनुमति और किसकी मिलीभगत से खड़ी हो रही हैं? क्या केडीए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह लापरवाही किसी दिन जानलेवा साबित हो सकती है।स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र में बने सभी बहुमंजिला निर्माणों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई हो और अवैध निर्माणों को तत्काल सील या ध्वस्त किया जाए, ताकि शहर को किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके।

> अवैध निर्माण की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में प्रवर्तन से रिपोर्ट मांगी गई है.
>
> **अभय पांडेय**
> सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण

स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इमारतें न तो निर्माण मानकों पर खरी उतरती हैं

और न ही सुरक्षा, फायर सेफ्टी, सेटबैक और भार वहन क्षमता जैसे जरूरी मानकों का पालन करती हैं। इसके बावजूद निर्माण खुलेआम जारी है। आरोप है कि केडीए के जिम्मेदार अधिकारी, इंजीनियर और सुपरवाइजर आंख मूंदे हुए हैं और पैसे के दम पर इन मौत की इमारतों को खड़ा होने दिया जा रहा है।

इलाके में करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी इमारतें बताई जा रही हैं, जिनमें कहीं काम चल रहा है तो कहीं हाल ही में निर्माण पूरा हुआ है। घनी आबादी, संकरी गलियां और आपात स्थिति में निकासी के रास्तों का अभाव स्थानीय लोगों के लिए स्थायी डर बन चुका है। बावजूद इसके, दहशत और दबाव के चलते लोग खुलकर शिकायत करने से बचते हैं।

सम्पादकीय

दमन से समाज में असंतोष गहरा होगा

ईरान में दशकों से जारी कट्टरपंथी शासन में गाहे-बगाहे प्रतिरोध के स्वर उभरते रहे हैं, जिनका दमन भी शक्ति से होता रहा है। लेकिन मौजूदा विरोध पिछले एक दशक में सबसे तीव्र है। प्रदर्शनकारियों के दमन और प्रदर्शनकारियों को मृत्यु दंड देने की चेतावनी के बाद नहीं लगता है कि जन-अशांति कम होगी। प्रदर्शनकारियों को 'ईश्वर का शत्रु' बताने की ढाल ईरानी सत्ताधीशों को किस हद तक सुरक्षा कवच मुहैया कराएगी,कहना कठिन है। ये महज तात्कालिक उद्देश्य ही किसी हद तक पूरा कर सकता है। इतिहास गवाह है कि दमन से व्यापक असहमति को शायद ही कभी दबाया जा सका हो। जब भी सत्ताधीशों ने ताकत के बल पर जनभावनाओं का दमन किया, फौरी तौर पर भले ही वह दबता दिखता हो, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। भीतर-ही-भीतर आक्रोश सुलगता रहता है। कालांतर वह अधिक वेग से वापस लौटकर सत्ता में बदलाव लाता है। दुनिया में तमाम उदाहरण विभिन्न देशों में सामने आते हैं। वास्तव में ईरान का संकट एक एकीकृत धर्म आधारित सत्ता और खुलेपन की ओर बढ़ते समाज का टकराव है। विशेष रूप से सत्ता और युवा वर्ग के बीच खाई लगातार चौड़ी हुई है। ईरान के युवा दूसरे इस्लामिक व मध्यपूर्व के अन्य देशों में खुले समाज और विकास की नई ऊंचाइयों से प्रभावित हैं। वे अपने देश में ऐसा ही प्रगतिशील शासन देखने के आकांक्षी हैं। ये युवा गरिमामय जीवन, अधिक आर्थिक उन्नति के अवसर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, मौजूदा लोकतांत्रिक विश्व में सत्ता द्वारा संवाद के बजाय शक्ति पर निर्भरता, उसकी उस वैधता को ही कमजोर करती है, जिसे वह अपने हित में संरक्षित करना चाहती है। शासन द्वारा जनता की आवाजों को दबाने का उपक्रम अस्थायी शांति तो ला सकता है, लेकिन शासन के प्रति अविश्वास को बढ़ाता है और अलगाव की खाई को गहरा करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान सरकार की दमनकारी नीतियों से वैश्विक समुदाय असहज महसूस कर रहा है। हालांकि, ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के दुराग्रहों का शिकार रहा है, वे जब-तब ईरान सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बजाय भू-राजनीतिक हितों से ज्यादा प्रेरित रही है। ईरान की परमाणु नीति के चलते उस पर व्यापक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिससे धीरे-धीरे ईरान की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई। फलस्वरूप महंगाई की मार से त्रस्त जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव से स्थितियों में कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी ज्यादा कष्टकारी हो चली है। तेहरान के साथ भारत के कूटनीतिक व आर्थिक संबंध बेहतर रहे हैं, मौजूदा स्थिति में भारत को ईरान के साथ सावधानी के साथ संतुलित संबंध बनाये रखने होंगे। जिसे ईरान के आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि दमन से व्यापक असहमति को शायद ही कभी दबाया जा सका हो। जब भी सत्ताधीशों ने ताकत के बल पर जनभावनाओं का दमन किया, फौरी तौर पर भले ही वह दबता दिखता हो, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। भीतर-ही-भीतर आक्रोश सुलगता रहता है।

विदेश नीति के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरता देश

यशवंत सचदेव

देश के लिए यह दौर विदेश नीति के मामले में चुनौतीपूर्ण है। विश्व स्तर पर यही स्थिति है। सबसे शक्तिशाली भागीदार अमेरिका के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध सबसे खराब दौर में हैं। जाहिर वजह तो टैरिफ व रूसी तेल खरीद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को एक पुराने मित्र देश और उभरती क्षेत्रीय ताकत की भी परवाह नहीं।वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए परमाणु परीक्षणों के बाद -जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे और परस्पर संवाद लगभग बंद हो गया था- यह पहली बार है जब अपने सबसे शक्तिशाली इस भागीदार के साथ भारत के संबंध खतरनाक रूप से नए निचले स्तर पर हैं। पिछले कुछ दिनों में, व्हाइट हाउस के उच्चतम गलियारों से तंज कसे गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक निवेदन करने वाले के रूप में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा : 'सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं'।

हां, माना जाता है कि अमेरिका की 'महान श्वेत आशा' ने उत्तर दे दिया। पछली बार जब एक प्रधानमंत्री -डॉ. मनमोहन सिंह- को एक अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष विनीत जैसा पाया गया था (2008 में उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कहा : 'भारत आपसे प्यार करता है'), तो देश में गुस्से का विस्फोट होना वाजिब था। सिर्फ 24 घंटे पहले, विदेश मंत्रालय ने मोदी द्वारा कही कथित बात को खारिज कर दिया। लेकिन संबंधों का यूं रसातल में जाते देखना बहुत बुरा लगा। एक चमकदार अतीत से जुड़ी अद्वितीय और महान सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय अभिजात वर्ग का अमेरिका द्वारा जिस प्रकार उपहास उड़ाया जा रहा है, महज इसलिए कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की हिम्मत दिखाई- इस मामले में, कुछ अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने से इंकार करना और सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने से मना करना -वह बहुत परेशान करने वाला है। जैसा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने एक पत्रकार से कहा, अमेरिकी प्रशासन ने भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी थी। इसके सिलसिले में मोदी को व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को फोन कर समझौते पर हस्ताक्षर की रजामंदी जाहिर करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने फोन कॉल नहीं की। आखिरकार, जब भारतीय पक्ष ने संपर्क किया, तो लटनिक ने उनसे कहा : 'बहुत देर हो चुकी है'। निश्चित रूप से, इसमें कुछ भी नया नहीं। भारत तो विशेष रूप से पश्चिमी नेताओं के सम्राटों की तरह पेश आने और अपना दबदबा दिखाए जाने का आदी है। विदेश मंत्रालय के अंदर, और बाहर भी, हर कोई उस दोगलेपन को समझता है जो बड़ी शक्तियों द्वारा खासकर शीत युद्ध के दौरान बरता जाता रहा, मीडिया ने उन्हें बेनकाब करने में कमी नहीं छोड़ी। समस्या यह है कि कम से कम पिछले 20 सालों से, भारत सोचता था कि वह अमेरिकियों के साथ खड़ा है। हमने उनका हास-परिहास अपनाया, हमारे बच्चे उनके कॉलेजों में गए -भारतीय माता-पिता ने अपना पेट काटकर उन्हें वहां भेजने के वास्ते डॉलर खरीदने के लिए बचतें की- और हमारी आईटी विशेषज्ञ पीढ़ी ने अमेरिका को बारंबार महान बनाने के लिए एचवन-बी वीजा लगवाया। हम बराबरी के थे। या कम से कम हम ऐसा सोचते रहे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जोकि मोदी मंत्रिमंडल के सबसे समझदार लोगों में से एक हैं, पुराने भारत के नए भारत में रूपांतरित होने में भूमिका निभा चुके हैं। भारत के शीर्ष राजनयिकों में से एक होने के नाते उन्हें दोनों पक्षों के लोगों से दोस्ती करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। जयशंकर के पिता के. सुब्रमण्यम ने तो 1971 में, बांग्लादेश युद्ध से पहले,पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के 'अत्यधिक झुकाव' के लिए तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को खरी-खरी सुनाई थी (सुब्रमण्यम ने किसिंजर से पूछा था,।

स्मरण शक्ति और एकाग्रता भी बढ़ती है नमस्कार से

अंतर्मन

डा0 सुधीर कुमार

भारत के अलावा कई देशों में भी नमस्कार की मुद्रा को अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। जापानी भाषा में इसे 'गाशो' कहा जाता है। भारत समेत कई देशों का यही मानना है कि हाथ जोड़ना केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक मनोस्थिति को भी दर्शाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार, हमारे हाथ ऊर्जा के उत्सर्जन केंद्र हैं। जब नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़े जाते हैं तो मन को असीम शांति मिलती है। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को जोड़ा जाता है। भारत के अलावा कई देशों में भी नमस्कार की मुद्रा को अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। जापानी भाषा में इसे 'गाशो' कहा जाता है। भारत समेत कई देशों का यही मानना है कि हाथ जोड़ना केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक मनोस्थिति को दर्शाता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी अंगुलियों के सिरे एक-दूसरे पर दबाव डालते हैं।

ये प्रेशर प्वाइंट्स हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़े होते हैं जो स्मरण शक्ति और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं जापान में 'गाशो' के माध्यम से यह बताया जाता है कि जब दाएं और बाएं हाथ आपस में मिलते हैं, तो ये दो विपरीत चीजों के मिलन के प्रतीक होते हैं जैसे स्वयं और दूसरा, प्रकाश और अंधकार। इनसे यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हम अलग-अलग नहीं हैं। गाशो की मुद्रा में व्यक्ति का मन भटकना बंद कर देता है। मन एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए अक्सर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कराई जाती है।

हमारे देश में जब कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो पहले दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण किया जाता है। ऐसा करने से मस्तिष्क की ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और जिस कार्य को किया जाने वाला है, उसे बल मिलता है। हाथ जोड़ने का सही तरीका यह है कि दोनों हथेलियों को अपने हृदय चक्र के पास सटाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से हृदय सकारात्मक होता है। हृदय को यह अहसास होता है कि नकारात्मक बिंदुओं को बाहर निकालना है और सकारात्मक बातों को अपने अंदर रखना है। यही कारण है कि जो लोग विनम्रता में हाथ जोड़कर बातें करते हैं, अथवा किसी विवादास्पद मुद्दे को हाथ जोड़कर खत्म करते हैं तो हाथों की सकारात्मक तरंगें निकलकर परिवेश में घुल जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ऐसे में वे प्रार्थना की मुद्रा किस प्रकार बनाएं? इस दर्द को समझा प्रणव वेम्पाती और उनकी टीम ने। प्रणव वेम्पाती, हर्षा रेड्डी पोंगुलेटी और सुरेन मरुममुला द्वारा वर्ष 2018 में एक स्टार्टअप की स्थापना की गई। वे मिसाइलमैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने कलाम से संबंधित कलार्म बनाने की सोची। आज भी देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो कृत्रिम अंगों विशेषकर कृत्रिम हाथों को खरीदने में असमर्थ हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने हृदय रोग के लिए प्रसिद्ध और किफायती 'कलाम स्टेंट' विकसित किया था। इसी स्टेंट के तर्ज पर प्रणव वेम्पाती ने एक ऐसा कृत्रिम हाथ बनाने का निश्चय किया जो लोगों के लिए सुलभ हो सके और वे लोग जिनके हाथ नहीं हैं, वे उसका प्रयोग कर न केवल अपने दैनिक कार्य कर सकें, अपितु दोनों हाथों के माध्यम से प्रार्थना कर अपने हृदय को भी मजबूत कर सकें। इसके लिए प्रणव को हर्षा और सुरेन जैसे सह-संस्थापक मिले। समान सोच के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया।विकसित देशों में उन्नत कृत्रिम बायोनिक हाथों की कीमत 35 से 60 लाख तक होती है। प्रणव सबसे सस्ता बायोनिक हाथ बनाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 'कलार्म' नामक 3डी-प्रिंटेड हाथ बनाया है। यह 18 तरह की ग्रिप देता है, ईएमजी सेंसर से चलता है और 8 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसकी कीमत अन्य देशों के मुकाबले

राढ़ा गौशाला की पोल खुली

मृत गोवंश को नोचते रहे कुत्ते

वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, जांच से पहले हटाया गया शव

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। विकासखंड बिल्हौर के राढ़ा गांव स्थित गौशाला में अव्यवस्थाओं की गंभीर तस्वीर सामने आई है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गौशाला परिसर के अंदर मृत गोवंश का शव खुले में पड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है और किसने बनाया, इसकी पुष्टि स्वराज इंडिया नहीं करता है।

वीडियो सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार रंजीत यादव और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) नेमचंद्र मौके पर पहुंचे, लेकिन सूत्रों के अनुसार उनके पहुंचने से पहले ही गौशाला कर्मियों द्वारा शव को हटाकर निस्तारण कर दिया गया। इससे पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में न तो पर्याप्त चारा-पानी की व्यवस्था है और न ही नियमित देखरेख। उनका कहना है कि लापरवाही के कारण गोवंश बीमार पड़ रहे हैं और समय पर उपचार न मिलने से उनकी मौत हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान शर्मिला देवी और पंचायत सचिव पर भी व्यवस्थाओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सक का नियमित निरीक्षण नहीं होता और कागजी कार्रवाई में व्यवस्थाएं दुरुस्त दर्शा दी जाती हैं। गौरतलब है कि राढ़ा गौशाला पूर्व में भी अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रही है, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन से स्थिति नहीं सुधरेगी, जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है।

सवालों से बचते नजर आए बीडीओ नेमचंद्र

मामले में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) नेमचंद्र से फोन पर पक्ष जानने का प्रयास किया गया। गौशाला का नाम सुनते ही उन्होंने बातचीत टालते हुए कहा कि "अभी बात करते हैं, एसडीएम का फोन आ रहा है," और फोन होल्ड पर रखकर अन्य कर्मचारी से चर्चा करते रहे। दोबारा संपर्क करने पर उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी खुलकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अधिकारी ही स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से परहेज करेंगे तो व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

एक नजर में...

- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मृत गोवंश को कुत्तों द्वारा नोचते दिखाया गया
- प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने से पहले हटाया गया शव
- चारा-पानी और इलाज की कमी का ग्रामीणों ने लगाया आरोप
- ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर लापरवाही के आरोप
- बीडीओ नेमचंद्र ने मीडिया के सवालों से बनाई दूरी
- जांच के बाद कार्रवाई का प्रशासन ने दिया आश्वासन

फर्जी दस्तावेजों से कृषि भूमि की बिक्री, दो आरोपी गिरफ्तार

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील क्षेत्र में फर्जी कागजों के सहारे कृषि भूमि की बिक्री करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो अन्य नामजद आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

जानकारी के अनुसार नानामऊ गांव निवासी निशांत कुमार ने पिछले वर्ष दिसंबर में बिल्हौर कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गांव स्थित उनकी कृषि भूमि (आराजी संख्या 502) का बैनामा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया है।

आरोप है कि गांव के अविरल सिंह ने असली भूमिधर के स्थान पर अपनी फोटो लगाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उन्हीं के आधार पर भूमि का विक्रय अभिनव मिश्रा के नाम करा दिया। शिकायत में शिवराजपुर निवासी रौनक शुक्ला और नानामऊ निवासी रवि कुमार पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि दोनों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर कथित फर्जीवाड़े को अंजाम देने में सहयोग किया।

- असली मालिक की जगह लगाई गई दूसरी फोटो, फर्जीवाड़ा कर कराई रजिस्ट्री
- दो आरोपियों को जेल, फरार दो की तलाश में पुलिस की दबिश

थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर नानामऊ से लोधनपुरवा मार्ग पर रामसिंह की चक्की के पास से अविरल सिंह और अभिनव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है और शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

किराए के कमरे में धमाका, युवक झुलसा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव में मंगलवार देर रात एक किराए के कमरे में अचानक हुए तेज धमाके से अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कमरे की दीवारें चटक गईं और छत का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कमरे में मौजूद युवक झुलसकर घायल हो गया, जबकि बाहर बंधी तीन बकरियों में से दो की मलबे में दबकर मौत हो गई।

- गैस रिसाव होने पर माचिस जलाते ही हुआ विस्फोट

जानकारी के अनुसार शिवराजपुर के दुबियाना गांव निवासी रमेश चंद्र नयापुरवा में रमा शुक्ला के मकान में किराए पर रहकर एक निजी कंपनी में कार्यरत है। मंगलवार रात वह रोज की तरह कमरे में सोने गया था। देर रात धूम्रपान के लिए जैसे ही उसने माचिस जलाई, अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए।

विस्फोट के कारण कमरे की दीवारों में दरारें पड़ गईं और प्लास्टर व मलबा नीचे गिर पड़ा। मलबे की चपेट में आने से रमेश घायल हो गया और झुलस गया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए भेजा।

इसी दौरान मकान के बाहर बंधी रमा शुक्ला के भाई राजेश शुक्ला की तीन बकरियां दीवार गिरने से दब गईं। ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाया, लेकिन तब तक दो बकरियों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक को सुरक्षित निकाल लिया गया।

- मंगलवार देर रात हुआ हादसा, चौबेपुर थाना क्षेत्र के नया पुरवा मजरे में
- घरेलू गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद जोरदार विस्फोट
- धमाके से कमरे की छत और दीवारें हिल गईं, मकान को भारी नुकसान
- कमरे में सो रहा बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती
- दो बकरियों की मौके पर ही मौत
- खाना बनाने के बाद गैस बंद करना भूलने से रिसाव की आशंका
- सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच
- घायल का इलाज जारी, हालत गंभीर बताई जा रही
- प्रशासन ने लोगों से गैस सिलेंडर के उपयोग में सावधानी बरतने की अपी

ग्रामीणों का अनुमान है कि कमरे में गैस रिसाव हो गया था और माचिस जलाते ही गैस ने विस्फोट का रूप ले लिया। हालांकि धमाके के बाद गैस निकल जाने से आग नहीं फैली और बड़ा हादसा टल गया।

पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी। घायल का इलाज कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

तटबंध बनाओ के नारे के साथ निकली जन चेतना पदयात्रा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

तटबंध हमारा, निर्माण हमारा नारे लगाते हजारों युवा और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए

फर्रुखाबाद। तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार 11 फरवरी को कढ़हर से अमृतपुर तक तटबंध निर्माण की मांग को लेकर विशाल जन चेतना पदयात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा में हजारों की संख्या में युवा और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। प्रतिभागी तटबंध संबंधी स्लोगन लिखी टी-शर्ट पहनकर और झंडे लेकर ‘तटबंध हमारा, निर्माण हमारा’ जैसे नारों के साथ आगे बढ़ते रहे।

समिति के अध्यक्ष भईयन मिश्रा ने बताया कि पदयात्रा कढ़हर से शुरू होकर सरी सवासी, खुटिया, बाराखेड़ा, अंतर, अर्जुनपुर, ज्ञानपुर, सलेमपुर होते हुए भरका पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद 12 फरवरी की सुबह यात्रा भरका से पुनः प्रारंभ होकर तारापुर, चाचूपुर, जमापुर, गोटिया, इमादपुर, रामपुर, जोगराजपुर होते हुए अलीगढ़ तिराहे तक पहुंचेगी और वहां से अमृतपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अमृतपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद उप जिलाधिकारी अमृतपुर को सौंपा जाएगा।

समिति पदाधिकारियों ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आंदोलन बताया और कहा कि जिस प्रकार से लोगों का उत्साह और समर्थन मिल रहा है, उससे तटबंध निर्माण की मांग को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है।

यात्रा में राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव प्रताप सिंह ने भी यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर समर्थन दिया। इसके अलावा नितेश मिश्रा, अनूप प्रधान, अनमोल अग्निहोत्री, दारापुर प्रधान, बहादुरपुर प्रधान, बदनपुर प्रधान, विपिन तिवारी, अनूप मिश्रा, संजीव अग्निहोत्री समेत कई लोगों ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर पदयात्रा के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रशांत पाठक (बमियारी) अपनी टीम के साथ क्षेत्र से लोगों को लेकर पहुंचे। वीरपुर हरिहरपुर निवासी सोनू सिंह ने भी अपनी टीम के साथ सक्रिय भूमिका निभाई।

पंकज राठौर, राजीव वर्मा, धर्मवीर राजपूत, शान खान, आदिल खान, अतीक खान, नरसिंह राजपूत सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने में जुटे रहे।

हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने भी यात्रा को समर्थन दिया और कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव संपर्क किया।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धीरज पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर लाला और जिला अध्यक्ष सावन मिश्रा ने भी अपनी टीम के साथ पदयात्रा में भागीदारी निभाई। समिति का कहना है

कि तटबंध निर्माण की मांग को लेकर यह जन चेतना पदयात्रा क्षेत्र की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है।

मतदाता सूची की खामियां दूर करने को एईआरओ को प्रशिक्षण

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी व नो-मैपिंग मामलों के सत्यापन की प्रक्रिया समझाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बिल्हौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मंगलवार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम डॉक्टर संजीव ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) व अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में 6 एईआरओ और 9 अतिरिक्त एईआरओ को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी व नो-मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि बीएलओ द्वारा सुनवाई के बाद अपलोड किए गए दस्तावेजों का एईआरओ लॉग-इन से सत्यापन कर अनुमोदन करना होगा।प्रशिक्षण सत्र में पोर्टल संचालन, दस्तावेजों की जांच और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाए रखें।

डेरापुर के गोवंश आश्रय स्थलों पर डीएम का बड़ा एक्शन

12 स्थलों की 21 बिंदुओं पर औचक जांच, एक सप्ताह में सुधार के निर्देश

- डेरापुर के 12 गोवंश आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण
- 12 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने की जांच
- 21 बिंदुओं पर व्यवस्थाओं की समीक्षा
- कई स्थानों पर चारा, साफ-सफाई व अभिलेखों में कमी मिली
- एक सप्ताह में सुधार के निर्देश
- लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
- गोवंश संरक्षण में व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के संकेत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। तहसील डेरापुर में संचालित गोवंश आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी कपिल सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील समाधान दिवस के बाद उनके निर्देश पर डेरापुर क्षेत्र के 12 गोवंश आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण कराया गया। इसके लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिन्होंने 21 बिंदुओं पर स्थलीय जांच कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

प्रत्येक अधिकारी को अलग-अलग गांवों की जिम्मेदारी सौंपी गई। निरीक्षण में गोवंशों की वास्तविक संख्या, ईयर टैगिंग, भूसा व हरे चारे की उपलब्धता, चोकर, नादों की स्थिति, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, टीकाकरण, जल निकासी, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, कर्मचारियों का विवरण, बाउंड्री वॉल, स्टॉक पंजिका, पहुंच मार्ग, बीमार व मृत पशुओं का विवरण तथा ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारी की भूमिका आदि की जांच की गई।जांच के दौरान कई स्थलों पर भूसा, हरा चारा व चोकर की कमी, साफ-सफाई में लापरवाही, हरे चारे के स्रोत का स्पष्ट अंकन न होना तथा स्टॉक पंजिका के सही संधारण में खामियां पाई गईं।इन कमियों को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि गोवंश संरक्षण शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व संबंधित समितियों को नियमित एवं औचक निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर ईंट-चाकू से हमला

- संविदा लाइनमैन घायल, जेई की तहरीर पर केस दर्ज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बकाया बिल पर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर गांव में हमला कर दिया गया। हमलावर ने गालीगलौज के बाद संविदा लाइनमैन पर ईंट और चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में जेई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

घटना सटटी विद्युत उपकेंद्र के नौबादपुर ग्रामीण फीडर से जुड़े मुजम्मनपुर गांव की है। संविदा लाइनमैन चंदन सिंह अपनी टीम ओमप्रकाश, चंद्रशेखर, अंशुल, राजकुमार और शिवम के साथ ओटीएस (एकमुश्त समाधान) योजना का प्रचार-प्रसार और बकायेदारों के कनेक्शन काटने के अभियान पर गांव पहुंचे थे।

बताया गया कि मुजम्मनपुर निवासी मनीष कुमार को पूर्व में ही बकाया बिल जमा करने की सूचना दी गई थी। भुगतान न होने पर टीम ने नियमानुसार उसका बिजली कनेक्शन काट दिया। इसी से नाराज होकर आरोपी ने बिजली कर्मचारियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी और संविदा लाइनमैन चंदन सिंह पर ईंट व चाकू से हमला कर दिया। हमले में लाइनमैन घायल हो गया। घटना के बाद टीम ने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी और सटटी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। राजपुर के जेई केडी वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

सभी विद्यालयों में मीना मंच कॉर्नर किए जाएं स्थापित

- मलासा बीआरसी में मीना मंच प्रशिक्षण का समापन, शिक्षकों को प्रमाण पत्र मिले

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा विकासखंड के बीआरसी परिसर में आयोजित दो दिवसीय मीना मंच प्रशिक्षण कार्यशाला का मंगलवार को समापन हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण ने सभी विद्यालयों में मीना मंच कॉर्नर स्थापित कर गतिविधियों को स्कूल की तरह नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीना मंच बालिकाओं को सशक्त बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और शिक्षा से जोड़कर रखने का प्रभावी माध्यम है।

प्रशिक्षण की शुरुआत मास्टर ट्रेनर अखिलेश कुमार ने प्रेरक गीत ÷मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है÷ से की। उन्होंने बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव, रचनात्मक लेखन, नेतृत्व क्षमता, सोशल मीडिया के प्रभाव और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं मास्टर ट्रेनर रिचा ने पोषणयुक्त आहार, जंक फूड से दूरी, माहवारी के दौरान स्वच्छता और डेंगू-फाइलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम पर जागरूक किया।

एआरपी अश्वनी कटियार ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, जेंडर समानता और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ मीना मंच की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने शत-प्रतिशत नामांकन और बच्चों की जिज्ञासाओं के समाधान पर बल देते हुए एक लघु फिल्म भी दिखाई। समापन सत्र में प्रतिभागी शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जितेंद्र, आशीष, सोहन, अरविंद, अर्पित, अंकित सहित कई शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

मीना मंच प्रशिक्षण कार्यशाला में समावेशी कक्षा निर्माण पर हुआ संवाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद। मीना मंच कार्यशाला के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद स्तर पर बाल उत्सव के लिए चयनित छात्र-छात्राओं के समकर्ता शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह के संरक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ. अर्चना मिश्रा द्वारा सम्मानित किया गया।

बदलाव की कहानी पर आधारित वीडियो एवं कॉमिक बुक गतिविधियों में जनपद स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं के पांच समकर्ता शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया गया। नोडल डॉ. अर्चना मिश्रा ने कहा कि यह सम्मान समकर्ताओं द्वारा बच्चों में बोए गए सकारात्मक संस्कारों और मूल्यों की पहचान है, जो आगे चलकर फलदायी सिद्ध होंगे।

नवाचार एवं प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, समूह में साझा करना तथा टूल-10 को नियमित अपडेट करने के बारे में जानकारी दी गई। राज्य अवार्डी मास्टर ट्रेनर नवीन दीक्षित ने कॉमिक बुक में विज्ञापनों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की। मास्टर ट्रेनर आनंद प्रकाश ने वीरांगना पोर्टल और कॉमिक बुक से संबंधित आवश्यक जानकारियां साझा कीं।

कार्यक्रम में स्वाती मिश्रा, नीलम चंदेल, तृप्ति दीक्षित, रिजवान खान, कल्पना द्विवेदी, सूर्य प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, मदन मोहन पाठक, सलिल द्विवेदी, प्रवीण अवस्थी, वंदना दोहरे सहित अनेक शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेनडाजोल दवा खिलाई गई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात. ।अकबरपुर ब्लाक के तिगाई स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को एल्बेनडाजोल दवा खिलाई गई। शासन के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत व गैर पंजीकृत बच्चों को आंगनबाड़ी संचालिका शैलेश दीक्षित द्वारा दवा का सेवन कराया गया।इस दौरान मौजूद सुपरवाइजर शिल्पी और आर्या शर्मा ने अभिभावकों को बताया कि एल्बेनडाजोल बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट करने की सुरक्षित और प्रभावी दवा है। इसे साल में 1 या 2 बार देने से बच्चों में खून की कमी, पेट दर्द तथा शारीरिक व मानसिक विकास में आने वाली रुकावटों को रोकने में मदद मिलती है।कार्यक्रम के अवसर पर बच्चों को दाल, दलिया और रिफाइंड तेल का भी वितरण किया ।इस दौरान सरीना, सुशीला, सत्वती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

नाम, आयु व अभिभावक नाम की विसंगति पर नई नोटिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

सत्यापन करने के लिए तहसील बुलाए गए मतदाता

रसूलाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ट्रक्र) के अंतिम चरण में नाम, माता-पिता के नाम और आयु में विसंगति पाए जाने पर मतदाताओं को नई नोटिस जारी की जा रही है। बीएलओ द्वारा घर-घर नोटिस वितरित की जा रही हैं और संबंधित विवरण बीएलओ ऐप में दर्ज किया जा रहा है।

प्रक्रिया के तहत नोटिस मिलने के बाद बीएलओ मतदाता की फोटो, आधार कार्ड एवं आवश्यक विवरण मोबाइल ऐप में अपलोड करता है।

इसके बाद मतदाता को निर्धारित तिथि पर नोटिस लेकर तहसील पहुंचकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है।

जानकारी के अनुसार प्रत्येक बूथ पर लगभग 100 से 300 मतदाताओं को यह नोटिस जारी की जा रही है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सुधार प्रक्रिया तेज की गई है। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्य अंतिम दौर में है। यहां चकबंदी विभाग के अधिकारियों को ईआरओ की जिम्मेदारी दी गई है। ब्लॉक और नगर पंचायत स्तर पर भी सत्यापन कार्य हो रहा है, लेकिन अधिक भीड़ तहसील में देखी जा रही है।नगरीय क्षेत्र के सुपरवाइजर लेखपाल रवेंद्र कुमार ने बताया कि सभी बीएलओ को नोटिस उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस वितरण के बाद ऐप में प्रविष्टि और फोटो अपलोड की जाती है, फिर मतदाता या उसके परिजन को तहसील में उपस्थित

- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतिम चरण में नई नोटिस जारी
- नाम, माता-पिता के नाम और आयु में पाई गई विसंगति आधार
- बीएलओ द्वारा घर-घर नोटिस वितरण शुरू
- बीएलओ ऐप में फोटो, आधार व विवरण अपलोड अनिवार्य
- निर्धारित तिथि पर तहसील में ईआरओ के समक्ष सत्यापन जरूरी
- प्रति बूथ 100-300 मतदाताओं को नोटिस
- ब्लॉक व नगर स्तर पर भी जांच, फिर भी तहसील में बढ़ी भीड़
- मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रक्रिया जारी है।

जेसीबी व दो डंपर जब्त 1.90 लाख का जुर्माना

स्वीकृत सीमा से अधिक मिट्टी खनन पर कसा शिकंजा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत टास्कफोर्स ने तहसील सिकंदरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। स्वीकृत मात्रा से अधिक मिट्टी निकासी पाए जाने पर एक ईंट भट्ठा संचालक पर 1,90,800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा एक जेसीबी और दो डंपरों को पकड़ा गया।

खान अधिकारी के अनुसार, खनिज अनुभाग और राजस्व विभाग की

संयुक्त टीम ने ग्राम मानपुर और सलेमपुर बैना में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान एक ईंट भट्ठा फर्म द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी का खनन किया जाना पाया गया। टीम ने तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मशीनरी और वाहनों को जब्त कर लिया तथा अर्थदंड आरोपित कर राजकोष में जमा कराया ।अधिकारियों ने बताया कि शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ जनपद में सतर्क निगरानी रखी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक अभियान चलाकर अवैध खनन और परिवहन के मामलों में कुल 153 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एक नजर में

- तहसील सिकंदरा क्षेत्र में टास्कफोर्स की संयुक्त कार्रवाई
- स्वीकृत मात्रा से अधिक मिट्टी खनन का मामला उजागर
- एक जेसीबी और दो डंपर पकड़े गए
- संबंधित ईंट भट्ठा संचालक पर 1,90,800 रुपये का अर्थदंड
- खनिज विभाग व राजस्व टीम ने ग्राम मानपुर व सलेमपुर बैना में किया निरीक्षण
- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 153 लाख रुपये की वसूली
- शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ सतत अभियान
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

चांदी के मुकुट से सुसज्जित हुए भद्रेश्वर महादेव

भागवत कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात, माती।सरवनखेड़ा क्षेत्र स्थित प्राचीन एवं आस्था के केंद्र महादेव बाबा भद्रेश्वर मंदिर में उस समय दिव्य वातावरण का सृजन हो गया, जब वरिष्ठ समाजसेवी सोनू सिंह परिहार ने भद्रेश्वर महादेव को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से चांदी का भव्य मुकुट अर्पित किया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजन-अर्चन के मध्य जैसे ही महादेव को मुकुट धारण कराया गया, सम्पूर्ण मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गुंजायमान हो उठा।इसी क्रम में श्रीमद्भागवत कथा के सातवें एवं अंतिम दिवस पर सोनू सिंह परिहार कथा स्थल पर उपस्थित होकर श्रद्धापूर्वक कथा-रस का श्रवण किया। सातवें दिन भागवत आचार्य द्वारा श्रीकृष्ण के वैकुण्ठ गमन, महाराज परीक्षित मोक्ष एवं कलियुग में भक्ति की महिमा जैसे अत्यंत मार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। कथा पंडाल हरि-नाम संकीर्तन से गुंजायमान रहा। सातवें दिवस हवन-पूजन, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ कथा का विधिवत समापन हुआ। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आयोजन को ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अविस्मरणीय बताया।

हज यात्रियों का प्रशिक्षण, टीकाकरण 14 फरवरी को

कानपुर देहात के हज-2026 के चयनित यात्रियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम अमरौधा स्थित अन्जुमन मदरसा जीनतुल इस्लाम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल के मार्गदर्शन में जारी सूचना के अनुसार, हज यात्रा से पहले टीकाकरण और प्रशिक्षण सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए ।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी हज यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें और टीकाकरण कराएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कार्यक्रम में शामिल न होने वाले यात्रियों को आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

» 114 सांसदों के हस्ताक्षर

» निष्पक्षता के आरोपों के बीच ओम बिड़ला का आत्मनिर्णय, सदन से रहेंगे दूर

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। प्रस्ताव पर 114 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इस तरह प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य हो गया है।

विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा

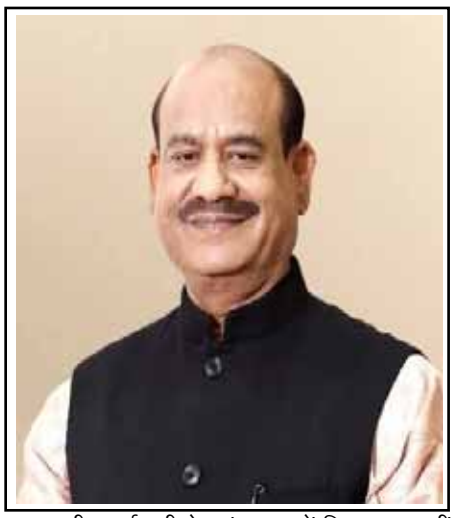

सदन की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी बातों को बार-बार अनदेखा किया जाता है और सरकार के पक्ष में झुकाव दिखाई देता है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया।

अब आगे की प्रक्रिया

लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रस्ताव की वैधता की जांच की जाएगी।

यदि प्रस्ताव नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो कम से कम 14 दिन बाद इस पर सदन में चर्चा कराई जाएगी। चर्चा के पश्चात लोकसभा में वोटिंग होगी। प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन इसके पक्ष में होगा।

स्पीकर का आत्मनिर्णय

सूत्रों के अनुसार, ओम बिड़ला ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होने के बावजूद उन्होंने यह आत्मनिर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार या विपक्ष की ओर से उन्हें मनाने के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहने के संकेत दे रहे हैं।

चर्चा की संभावित तिथि

संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही, यानी 9 मार्च को, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो सकती है।

114 सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ओम बिड़ला पद पर बने रहेंगे या हटेंगे, इसका अंतिम फैसला लोकसभा में होने वाली वोटिंग से ही तय होगा।

जांच में खुला राज: एनएच-730सी पर लाइटिंग के नाम पर सिर्फ पत्राचार, भुगतान शून्य

» आईजीआरएस जवाब से पर्दाफाश, आईपीसीएल बोला, 'एक रुपया भी जमा नहीं'

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। पांचाल घाट से बवर तक एनएच-730सी पर स्ट्रीट लाइट लगाने के दावों की परतें अब जांच में खुलने लगी हैं। आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से की गई शिकायत के जवाब में इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) ने साफ कर दिया है कि लाइटिंग कार्य के लिए अब तक परियोजना की ओर से कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई है।

अधिवक्ता एवं किसान नेता अशोक कटियार ने हाईवे पर अंधेरे की समस्या को लेकर आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि एनएच-730सी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा लाइटिंग संबंधी पत्र भेजे जाने का दावा किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। 10 फरवरी को आईपीसीएल ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि इस कार्य हेतु कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए काम प्रारंभ नहीं कराया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अलग से लिखित पुष्टि की कि संबंधित मद में एक रुपये की भी धनराशि सरकारी खाते में नहीं आई है।

सवालों के घेरे में कौन?

जांच के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि शासन स्तर से हाईवे पर प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे तो संबंधित परियोजना प्रबंधन ने धनराशि क्यों नहीं जमा कराई?। क्या केवल औपचारिक पत्राचार कर मामले को आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया?। क्या बजट स्वीकृत ही नहीं हुआ या स्वीकृति के बाद भी भुगतान रोका गया?। स्थानीय लोगों का कहना है कि पांचाल घाट से बवर तक का हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। यह मार्ग धार्मिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहीं अधिवक्ता अशोक कटियार ने पुनः आईजीआरएस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है कि कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? धनराशि किस स्तर पर अटकी? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है।

पांचाल घाट चौराहा पर लगा हाईवे का बोर्ड

दोनों पत्र जो अधिवक्ता के पास भेजे गए हैं

जांच में सामने आए प्रमुख बिंदु

» एनएच-730सी प्रबंधन की ओर से लाइटिंग का पत्र भेजे जाने का दावा

»आईपीसीएल का लिखित जवाब- भुगतान शून्य

» बिजली विभाग की पुष्टि- खाते में कोई राशि नहीं

» मौके पर लाइटिंग कार्य का कोई भौतिक प्रमाण नहीं

»आईजीआरएस के माध्यम से दोबारा जवाब तलब

'वंदे मातरम' पर केंद्र का नया प्रोटोकॉल, अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में छह छंद अनिवार्य

» जन गण मन से पहले होगा वंदे मातरम् का गायन, 3 मिनट 10 सेकंड की निर्धारित अवधि

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के संबंध में पहली बार विस्तृत और औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए प्रोटोकॉल के तहत अब वंदे मातरम् के पूर्ण छह छंद वाले संस्करण को सभी सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान जन गण मन दोनों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, तो पहले वंदे मातरम् और उसके बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया जाएगा। छह छंद वाले वंदे मातरम् की समयावधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है।

निर्देशों के अनुसार, वंदे मातरम् के गायन या वादन के दौरान उपस्थित सभी लोगों को सम्मान स्वरूप खड़ा होना अनिवार्य होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय गान के समय किया जाता है। हालांकि, यदि वंदे मातरम् किसी फिल्म या डॉक्युमेंट्री के हिस्से के रूप में सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होता है, तो वहां खड़े होने की बाध्यता लागू नहीं होगी।

सरकार ने स्कूलों में भी वंदे मातरम् के सामूहिक गायन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ किया जा सके।

यह पहली बार है जब वंदे मातरम् की प्रस्तुति को लेकर इतना विस्तृत और व्यवस्थित प्रोटोकॉल जारी किया गया है। सरकार का उद्देश्य इसके सम्मान और प्रस्तुति की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना बताया गया है।

इन अवसरों पर प्रस्तुति अनिवार्य

» नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम् का गायन/वादन निम्न अवसरों पर अनिवार्य होगा—

»सभी सरकारी और आधिकारिक समारोह

»तिरंगा फहराने के कार्यक्रम

»राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन एवं प्रस्थान समारोह

»नागरिक सम्मान समारोह

»अन्य सरकारी कार्यक्रम जहां राष्ट्रीय गीत का औपचारिक सम्मान किया जाता है

फरेब

अयोध्या में संतों के नाम पर साजिश

महंत की कुर्सी से करोड़ों की संपत्ति तक रची गई फर्जी दस्तखत की कहानी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या जहां धर्म, आस्था और संत परंपरा की जड़ें सदियों से गहरी रही हैं, वहीं अब उसी पवित्र परंपरा को छल, फरेब और कूटरचना से कलंकित करने की एक सनसनीखेज साजिश सामने आई है। जानकी निवास मंदिर से जुड़े महंत पद और संपत्ति विवाद में संतों के फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार किए गए महज्जरनामा ने पूरे धार्मिक समाज को झकझोर कर रख दिया है।

महंत पद और संपत्ति विवाद में संतों के फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार किए गए महज्जरनामा

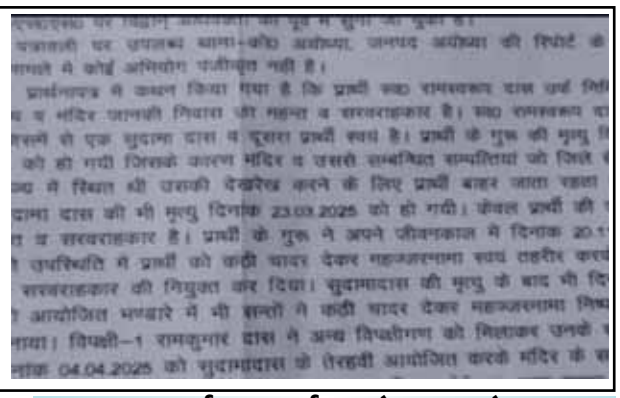

इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर के आदेश के बाद साफ हो गया है कि यह कोई साधारण विवाद नहीं, बल्कि सुनियोजित अपराध का जाल है जिसका मकसद मंदिर की महंताई और बहुमूल्य संपत्तियों पर कब्जा करना था। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता नेहा श्रीवास्तव के अनुसार, आरोपियों ने मंदिर की सत्ता हथियाने के लिए ऐसा रास्ता चुना, जिसमें संतों की आस्था को ही हथियार बना लिया गया। आरोप है कि प्रतिष्ठित संतों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। झूठा महज्जरनामा तैयार कराया गया इसे धार्मिक सहमति का रूप देने की कोशिश की गई और बाद में उप-निबंधक कार्यालय में पंजीकरण कराने का प्रयास हुआ इस फर्जीवाड़े में महंत कमल नयन दास सहित पांच संतों के नाम का दुरुपयोग किया गया। महंत कमल नयन दास और अन्य संतों ने नोटरी शपथपत्र देकर स्पष्ट किया कि फ़हमने किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए। दिखाए गए हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं।

एफआईआर दर्ज करने का आदेश

इस साजिश में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनमें शामिल हैं राम कुमार दास, संजय मिश्र, बलराम दास, सत्यम राम, आशीष, अशोक पाण्डेय और शिवम। इन सभी पर मिलकर षड्यंत्र रचने और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए कोतवाली अयोध्या को एफआईआर दर्ज करने निष्पक्ष विवेचना करने और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया कि मामला कूटरचना जालसाजी आपराधिक साजिश धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, जानकी निवास मंदिर से जुड़ी चल-अचल संपत्तियों की कीमत करोड़ों में है। महंत पद पर कब्जा मिलते ही इन संपत्तियों पर अधिकार स्वतः मिल जाता है। यही वजह है कि धर्म की आड़ संतों की पहचान और आस्था की मर्यादा सबको ताक पर रखकर यह साजिश रची गई। यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है क्या अब मंदिरों और मठों में भी माफियागिरी पैर पसार चुकी है?।

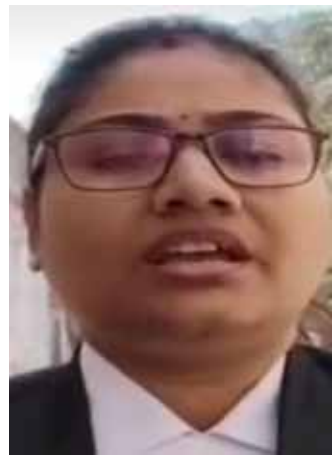

अधिवक्ता नेहा श्रीवास्तव

भंडारे की आड़ में षड्यंत्र

मामले की सबसे चौंकाने वाली परत 14 जुलाई 2025 की घटना से खुलती है। आरोप है कि भडारे का आयोजन किया गया संतों को कंठी और चादर पहनाई गई। धार्मिक माहौल बनाया गया और उसी बीच महज्जरनामा तैयार करने का नाटक किया गया ताकि बाद में इसे संतों की सहमति बताया जा सके। यानी धर्म की आड़ में दस्तावेजी धोखाधड़ी।

रास्ता बंद, सच दफन लेखपाल कटघरे में

फर्जी रिपोर्ट का खेल

» कोर्ट ने दिया लेखपाल समेत तीन पर एफआईआर के आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। वल्लीपुर गांव निवासी महिला की शिकायत पर गलत और फर्जी रिपोर्ट लगाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने लेखपाल मोतीलाल समेत तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

पीड़िता संगीता ने आरोप लगाया था कि उनके मकान तक जाने वाला रास्ता अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। इसे खुलवाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के दौरान संबंधित लेखपालों ने तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट लगाकर मामला दबाने का प्रयास किया। संगीता के अनुसार, फर्जी रिपोर्ट के चलते उन्हें लंबे समय तक न्याय से वंचित रखा गया। प्रशासनिक स्तर पर निराशा मिलने के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट देना कानूनन अपराध है और इससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। न्यायालय के आदेश पर अब कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करनी होगी। वहीं, कोर्ट के इस सख्त रुख से राजस्व विभाग में खलबली मच गई है। पीड़िता संगीता ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, इस मामले ने एक बार फिर सरकारी महकमे में चल रहे ÷रिपोर्ट के खेल÷ को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच में कितनी सच्चाई सामने आती है और दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।

डीएम ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कई जगह अव्यवस्थाएं मिली

» नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अफसरों को दिए कई निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने शासन के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी नगर, प्रशासन, वित्त एवं राजस्व, नजारत, निबंधन, आपदा प्रबंधन समेत अन्य पटलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और भवन मरम्मत की स्थिति देखी। कई स्थानों पर अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने अभिलेखों के रखरखाव पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि फाइलों को क्रमबद्ध और सुरक्षित रखा जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। विद्युत तारों की अव्यवस्थित स्थिति और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी डीएम ने सख्ती दिखाई और शीघ्र सुधार के आदेश दिए। पूरे परिसर में साफ-सफाई के अलावा डस्टबिन लगाने, लोगो के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था और सभी कार्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को कहा गया। निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

राम मंदिर परिसर में पहली बार भव्य महाशिवरात्रि

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर परिसर में इस वर्ष पहली बार महाशिवरात्रि का पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में 15 फरवरी को परकोटे के छह मंदिरों में दक्षिण-पश्चिम दिशा में निर्मित शिवालय के शिखर पर ध्वजारोहण प्रस्तावित है। हालांकि मुख्य अतिथि का नाम तय न होने के कारण अभी कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना है कि किसी वरिष्ठ संत द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार कुबेर नवरत्न टीला स्थित कुबेरेश्वर महादेव और परकोटे के शिवालय में विशेष अभिषेक-पूजन किया जाएगा। इसके बाद भगवान शिव

का भव्य श्रृंगार होगा तथा सायंकाल आरती के साथ विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। रथ सप्तमी की तर्ज पर महाशिवरात्रि के दिन कुबेर टीला और परकोटे का शिवालय पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा अंगद टीला पर पार्थिव द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। सायंकाल भगवान शिव के विवाहोत्सव का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस दौरान शिव बारात परिसर के भीतर ही निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है, ताकि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जा सकें।

CAG की रिपोर्ट में खुलासा

कौशल विकास योजना में बड़ी खामियां

लाखों युवाओं को नहीं मिला भुगतान

योजना में करीब 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए की हेराफेरी का अनुमान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन, लाभार्थियों के डेटा, बैंक विवरण, भुगतान और रोजगार दावों में व्यापक अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित किए गए लाखों युवाओं के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां पाई गईं। कई मामलों में लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी अधूरी या संदिग्ध पाई गई। कुछ रिकॉर्ड में खाते के स्थान पर "11111111" या "123456" जैसे नंबर दर्ज मिले, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं।

निगरानी और वित्तीय नियंत्रण कमजोर

CAG ने योजना के संचालन में आईटी सिस्टम, आधार आधारित उपस्थिति, भौतिक निरीक्षण और वित्तीय निगरानी को अपर्याप्त बताया है। धन के उपयोग और प्रशिक्षण की गुणवत्ता की प्रभावी जांच नहीं होने से योजना की पारदर्शिता प्रभावित हुई। कौशल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही है। संसद में जानकारी दी गई कि कई प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। विपक्षी दलों ने रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि युवाओं के नाम पर चलाई जा रही योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

34 लाख से अधिक युवाओं को नहीं मिला प्रोत्साहन

CAG ने बताया कि योजना के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भुगतान (DBT) में गंभीर देरी हुई। लगभग 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को भुगतान लंबित पाया गया। कई मामलों में बैंक विवरण गलत होने के कारण राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी। ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ प्रशिक्षण केंद्र केवल कागजों पर सक्रिय थे, जबकि जमीनी स्तर पर वे बंद मिले। कुछ जगहों पर एक ही फोटो का इस्तेमाल अलग-अलग लाभार्थियों के रिकॉर्ड में किया गया। इससे प्रमाणन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

योजना की साख पर ही सवाल !

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन CAG की रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि योजना के क्रियान्वयन में प्रणालीगत खामियां हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से अमल करती है।

रोजगार दावों पर भी सवाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमाणित युवाओं में से केवल लगभग 40 प्रतिशत को ही रोजगार मिलने का दावा सत्यापित रूप में सामने आया। शेष मामलों में प्लेसमेंट का रिकॉर्ड या तो उपलब्ध नहीं था या प्रमाणित नहीं किया जा सका। CAG ने संकेत दिया कि प्रशिक्षण और रोजगार के बीच ठोस समन्वय की कमी रही।

ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी इस बात का किया था जिक्र

बात करने का लहजा पसंद नहीं आया तो ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ बढ़ाया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली (इंटरनेशनल डेस्क)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर आयात शुल्क (टैरिफ) 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत करने के अपने फैसले के पीछे एक असामान्य वजह बताई है। फॉक्स न्यूज/फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि स्विट्जरलैंड की एक महिला नेता से फोन पर हुई बातचीत का "लहजा" उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया।

ट्रंप ने बताया कि उनकी बातचीत स्विस फेडरल काउंसिल की सदस्य कैरिन कैलर-सटर से हुई थी। उनके मुताबिक स्विस पक्ष बार-बार यह दलील दे रहा था कि "स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है और इतना अधिक टैरिफ वहन नहीं कर सकता।" ट्रंप ने कहा कि उन्होंने साफ कर दिया कि देश छोटा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका व्यापार घाटा बड़ा है। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार घाटा करीब 38 से 42 अरब डॉलर के बीच बताया जाता है। ट्रंप ने इसी घाटे को कड़े टैरिफ का आधार बताते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से असंतुलित व्यापार का सामना कर रहा है। उनका आरोप था कि स्विट्जरलैंड अमेरिका में निर्यात तो कर रहा है, लेकिन "उचित टैरिफ" नहीं दे रहा।

बाद में समझौते की दिशा

टैरिफ बढ़ोतरी के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई। वॉशिंगटन में वार्ताओं के बाद टैरिफ दरों में कमी लाने की दिशा में सहमति बनी और दरों को घटाकर लगभग 15 प्रतिशत तक लाने की रिपोर्ट सामने आई, जिससे द्विपक्षीय निवेश और व्यापार संबंधों को स्थिरता देने की कोशिश की गई। यह प्रकरण इस बात का उदाहरण माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में आर्थिक तर्कों के साथ-साथ कूटनीतिक संवाद की शैली भी असर डाल सकती है।

"आक्रामक कॉल" का दावा

ट्रंप ने इंटरव्यू में दावा किया कि फोन कॉल का अंदाज "आक्रामक" था और बातचीत समाप्त करने में भी कठिनाई हुई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 30 प्रतिशत टैरिफ पर राहत देने के बजाय उन्होंने इसे बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी इस बातचीत का जिक्र किया था।

स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। वहां सात सदस्यों वाली फेडरल काउंसिल सामूहिक रूप से सरकार का नेतृत्व करती है और उसी में से एक सदस्य वार्षिक आधार पर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com